मेहनतकशों का पैग़ाम — मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com
Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

शिक्षिका उत्तरा पंत को अपमानित कराने वाला त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री है या कोई राजा जो आम लोगों से दरबार लगाकर मिलता है?

स्कूली बच्चों की सुरक्षा	3
निजीकरण और रामदेव	4
साये से भी डरेगा मोदी	5
टंडन की दलाली	8

वर्ष 31 अंक -27 फ़रीदाबाद 1-7 जुलाई 2018 फोन : - 9999595632 ₹ 2.50

सीमा त्रिखा ने डुबोई लुटिया भाजपा की, डैमेज कंट्रोल में लगे विपुल गोयल

फ़रीदाबाद (म.मो.) बिजली समस्या से परेशान ग्रीनफ़ील्ड के वासी आधी रात को फ़रियाद लेकर अपनी विधायक सीमा त्रिखा के आवास पर पहुंचे तो उन्होंने पुलिस बुलाकर 18 लोग़ों को हवालात में बंद करा दिया।

कई दिनों से बिजली की आंख मिचौनी से परेशान ग्रीनफ़ील्ड कॉलोनी के सैंकड़ो निवासी शुक्र-शनिवार की मध्य रात्रि को कारों से विधायक सीमा त्रिखा के सेक्टर 21 बी स्थित आवास पर प्रदर्शन करने पहुंचे। उनके प्रदर्शन का तरीका था, सभी कारें एक साथ हार्न बजा कर इतना शोर करें ता कि विधायक महोदया भी चैन की नींद न सो सकें। जाहिर है जब उनके क्षेत्र के लोग चैन की नींद न सो पा रहे हों तो वे उन्हें भी क्यों सोने देंगे?

सत्ता में भागीदार विधायक भला यह सब क्यों सहन करने लगी? लोग़ों ने एक बार वोट देकर उन्हें विधायक बना दिया तो क्या वे उन्हें रात को सोने भी नहीं देंगे? लिहाज़ा थाना एनआईटी को फ़ोन किया गया। जो पुलिस आसानी से किसी नागरिक की फ़रियाद पर हिलती डुलती नहीं, वह तुरंत दौड़ती हुई विधायक के आवास पर पहुंच गयी। (पुलिस का कहना मानते हुये प्रदर्शनकारियों ने अपनी गाड़ियां सेक्टर 46 स्थित बिजलीघर की तरफ़ मोड़नी शुरू ही की थी कि) पुलिस ने उन्हें रोक कर 18 लोग़ों को पकड़ कर और कूट-पीट कर अपनी

गाड़ियों में ठूंसना शुरू कर दिया और थाने लाकर, कपड़े उतवाकर रात करीब 3 बजे हवालात में बंद कर दिया। इन पर अमन चैन को हानि पहुंचाने की ह्लद्धड्डह्व द्यड्ड ।।द्मद्मशह्वद्म स्रद्ध धारा 107/151 लगाई गयी। शनिवार बाद दोपहर 3 बजे यानी 12 घंटे बाद सभी को हवालात से निकाल कर डीसीपी के सामने पेश किया गया जहां से उन्हें जमानत पर शाम को साढे 7 बजे छोड़ दिया गया।

क्षेत्र के निवासियों के साथ यह सब गुजर चुकने के बाद विधायक कहती हैं कि वे तो उस रात घर पर थी ही नहीं, वे तो एक शादी में गुड़गांव गयी हुई थी। घर पर तो केवल उनका पीएसओ (पर्सनल सिक्योरिटी अफ़सर) था। तो क्या यह सारी कार्यवाही एक हवलदार स्तर के पीएसओ के फ़ोन मात्र पर ही हो गयी? इस सफ़ेद झूठ को केवल वही मान सकते हैं जो मोदी के अंध-भक्त होंगे। यदि विधायक बाहर थी तो उनका पीएसओ उनके साथ होना चाहिये था, न कि उनके घर पर।

इसमें कोई दो राय नहीं कि इस सारे किये धरे का दायित्व थाना प्रभारी पर आता है, बेशक उसने यह काम किसी राजनेता या अपने ही उच्चाधिकारी के कहने पर किया हो। सभी जानते हैं कि पासा उल्टा पड़ने पर अक्सर आदेश देने वाले मुकर जाया करते हैं। फ़िर जिस डीसीपी के सम्मुख उन्हें 3 बजे पेश किया गया, क्या उन्हें इस सारे मामले का ज्ञान नहीं था? उनका दफ़्तर थाने से मात्र डेढ किलोमीटर के फ़ासले पर स्थित है। उन्होंने तुरन्त इस मामले का संज्ञान क्यों नहीं लिया? इतना ही नहीं 3 बजे पेश किये जाने पर भी उन्हें डिस्चार्ज (केस खत्म) करने के बजाय जमानतों पर ही छोड़ा। यह तो शुकर है कि वे सभी 18 आदमी बहुत भोले और संघर्ष से दूर रहने वाले थे, वरना कहीं वे जमानत देने से मना कर देते तो क्या होता? डीसीपी साहेबा उन्हें जेल भेज देती तो भाजपा की लुटिया तो और गहरी डूबती ही साथ में डीसीपी की भी।

विपुल गोयल का ड्रामाई डैमेज कंट्रोल

विधायक सीमा त्रिखा के कारनामों से यूं तो उनका बंटाधार पहले ही हुआ पड़ा था, परन्तु इस घटना ने तो उनके साथ-साथ शहर में भाजपा का भी बंटाधार कर दिया। इसे लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री तक परेशान हैं। पार्टी को पहुंचे इस भारी नुक्सान और वह भी चुनावी वर्ष में, इसकी भरपाई करने का बीड़ा स्थानीय विधायक एवं उद्योगमंत्री विपुल गोयल ने उठाया है।

उन्होंने सोमबार यानी 25 जून को बाकायदा प्रेसवार्ता करके इस घटना पर खेद प्रकट किया। इसके साथ-साथ उन्होंने प्रेस के सामने स्पीकर ऑन करके राज्य के पुलिस प्रमुख बलजीत सिंह संधू को इस घटना की जांच करने तथा थाना प्रभारी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के साथ उन्हें लाइन हाजिर करने को कहा। जवाब में डीजीपी ने कहा कि वे जांच करायेंगे।

इसके बाद इसी ढंग से थाना प्रभारी को हड़काते हुये भी बहुत कुछ कहा और गत 3 माह में वे इस थाने में दर्ज मुकदमों में की गयी कार्यवाही का ब्योरा दें। जाहिर है यह सब ड्रामा विपुल गोयल, पत्रकारों के माध्यम से जनता को दिखा कर यह सिद्ध करना चाह रहे हैं कि उन्हें जनता की कितनी चिन्ता है। एक विधायक ने यदि कुछ गलत करा भी दिया है तो बाकी पार्टी और खासतौर पर वे खुद जनता के साथ खड़े हैं।

सवाल यह खड़ा होता है कि थाना प्रभारी के विरुद्ध तो उन्होंने बड़े से बड़ी तोप चला दी, लेकिन उस विधायक महोदया के विरुद्ध पार्टी अथवा सरकार क्या करने जा रही है जिसने निरीह जनसमूह को उठा कर रात भर हवालात में बंद रखवाया? बेशक पार्टी उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न करे परन्तु समय आने पर जनता न केवल विधायक से बल्कि पूरी पार्टी से ही हिसाब चुकता कर लेगी। विपुल गोयल का डैमेज कंट्रोल ड्रामा भी कुछ काम आने वाला नहीं। ध्यान रहे कि कुछ अर्सा पहले इसी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री खट्टर का रोड शो धूमधाम से सम्पन्न कराने में सीमा त्रिखा अग्रणी थी। लोगों को तब इनकी कथनी और करनी में अंतर को लेकर अगर कोई भ्रम था तो अब सीमा के इस कारनामे से दूर हो गया होगा।

कैसे-कैसे पहुंचे सीमा त्रिखा के द्वारे

कॉलोनीवासियों की कोई योजना सीमा के घर पर जाने की नहीं थी। शुक्रवार की रात करीब 11 बजे बिजली की आंख मिचौनी से तंग आये निवासी अपने अध्यक्ष बिंदे के घर पर गये। उन्हें सोते से उठाया और बिजली अधिकारियों को फ़ोन करने को कहा। बिंदे ने तमाम छोटे अधिकारियों को फ़ोन मिलाने का विफ़ल प्रयास करने के बाद करीब 12 बजे एसई को कई बार फ़ोन लगाया लेकिन किसी ने नहीं उठाया। इस पर कॉलोनी वासियों ने स्थानीय 11 केवी बिजली घर की ओर चलने के लिये बिंदे को कहा। सभी लोग जब वहां पहुंचे तो वहां तैनात कर्मचारी ने बताया कि बिजली की सप्लाई पीछे से ही नहीं आ रही तो वह क्या कर सकता है? इस पर भड़के हुये लोग़ों ने हाइवे जाम करने की बात कही जिससे सारा प्रसाशन उठ खड़ा होगा और उनकी फ़रियाद सुनेगा। बिंदे ने उन्हें समझाया कि यह बहुत गलत काम होगा, जैसे-तैसे रात काट लो सुबह कोई न कोई इलाज करेंगे। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे।

ऐसे में बिंदे उन्हें समझा-बुझा कर स्थानीय पुलिस चौकी में ले गये। लेकिन वहां मौजूद एएसआई तालीम ने आक्रोशित भीड़ को समझाने-बुझाने की बजाय हाईवे जाम करने का सुझाव यह कहते हुये दिया कि इसके बाद सारी समस्यायें हल हो जायेंगी। लेकिन बिंदे ने भीड़ को समझा-बुझा कर सेक्टर 45 स्थित बिजली घर की ओर चलने के लिये तैयार कर दिया। रात के अंधेरे में पचासों कारों का काफिला अपनी ओर आते देख, डर के मारे पावर हाउस के कर्मचारी ताला लगाकर भाग खड़े हुये। क्योंकि इससे पहले भी वे मेवला महाराजपुर गांव के ऐसे ही काफिले से पिट चुके थे।

अब तक रात के दो बज चुके थे यहां से वापिस खाली हाथ लौटने की बजाय भीड़ ने सीमा त्रिखा के घर जाने का निर्णय ले लिया। स्पष्ट है कि यदि 12 बजे के आस-पास बिजली अधिकारियों ने फ़ोन उठा लिये होते या पुलिस चौकी वालों ने भीड़ को समझा-बुझा कर संतुष्ट कर दिया होता अथवा सेक्टर 45 वाले बिजली कर्मचारियों ने उनकी समस्या पर कोई बातचीत की होती तो ये लोग सीमा त्रिखा के घर जाने वाले नहीं थे।

सीमा के घर पहुंच कर बिंदे व कुछ लोग गेट पर गये, घंटी बजायी तो एक पुलिसकर्मी निकला। कॉलोनीवासियों की बात सुनकर उसने भड़कते हुये कहा कि यह कोई टाईम है आने का, भागो यहां से, सुबह आना। उसने यह बिल्कुल नहीं कहा कि विधायक महोदया घर पर नहीं हैं। पुलिस वाले का जवाब सुनकर पहले से ही भड़के हुये कॉलोनीवासी और भी गर्म हो गये और नारेबाज़ी शुरू कर दी। थोड़ी देर में बिंदे द्वारा समझाने-बुझाने पर लोग वापस चलने को तैयार हो गये। अधिकांश लोग वापस चल भी दिये थे, केवल 10-12 गाड़ियां ही बचीं थी जो हॉर्न बजाकर अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे थे।

पुलिस के 4-5 सिपाही उसी वक्त आ गये थे जब बिंदे विधायक के सुरक्षाकर्मी से बात कर रहे थे। लेकिन अधिक भीड़ को देखकर पुलिसकर्मियों ने भीड़ पर हाथ डालने के बजाय अतिरिक्त पुलिस बल मंगाया। जब तक यह अतिरिक्त बल आया बिंदे अधिकांश भीड़ को लेकर वापस कॉलोनी पहुंच चुके थे। बचे हुये 20-25 लोगों पर पुलिस बल ने जम कर अपना हाथ साफ़ किया। उन्होंने नहीं देखा कि पिटने वाला बुढ़ा है या जवान।

ग्रीनफ़ील्ड की बिजली समस्या से स्मार्ट सिटी का भद्दा चेहरा सामने

फ़रीदाबाद (म.मो.) अरावली की मनमोहक पहाड़ियों में करीब 60 वर्ष पूर्व एक कालोनाइज़र को सरकार ने कॉलोनी विकसित करने का लाइसेंस दिया था। कौड़ियों के भाव खरीदी ज़मीन को सोने के भाव बेचा गया। लेकिन कॉलोनाइज़र ने लाइसेंस की शर्तों के मुताबिक काम पूरे नहीं किये। उन्हीं कामों में से एक काम बिजली आपूर्ति का है।

लाइसेंस की शर्तो के मुताबिक कॉलोनी में बिजली के खम्बे, तार व ट्रांसफ़ार्मर आदि लगाने का दायित्व कॉलोनाइज़र का होता है। लेकिन यह सारा काम सरकारी बिजली विभाग की देख-रेख में तय शुदा मानकों के अनुरूप होना चाहिये। जब सरकारी बिजली विभाग कराये गये कार्य से संतुष्ट हो जाता है तभी वहां विभाग द्वारा बिजली की आपूर्ति शुरु की जाती है। कॉलोनाइज़र यह सारा काम तय मानकों के अनुसार न करके, बिजली अधिकारियों की मिलीभगत से खानापूर्ति के तौर पर करता रहा।

इस कॉलोनी में बिजली का नया कनेक्शन देना बिजली विभाग का काम है परन्तु रोजमर्रा की शिकायतों को हल करने के लिये कॉलोनाइज़र का अपना स्टाफ़ होता है। बिजली आपूर्ति का ढांचा (इन्फ्रासस्ट्रक्चर) इतना कमजोर एवं नकली है कि शिकायतें हल करने वाला स्टाफ़ बढती शिकायतों को दूर नहीं कर पा रहा। एक फ़ाल्ट को ठीक करता है तब तक दो और हो जाते हैं। ग्यारह केवी का ट्रांसफ़ार्मर जो कॉलोनाइज़र ने कभी लगाया था अब पर्याप्त नहीं रहा। गर्मी में बढती मांग से ओवरलोड होकर बंद हो जाता है।

बिजली विभाग के सूत्रों के अनुसार यहां पर 66 केवी का सब स्टेशन बनना चाहिये था जिसे बनायेगा तो बिजली विभाग लेकिन इसके लिये ज़मीन व पैसा कॉलोनाइज़र को देना होता है। इस काम के लिये ज़मीन विभाग को पिछले दिनों मिल गयी है जिस पर कार्य योजना स्वीकृति हेतु हिसार मुख्यालय भेजी हुई है। रही बात इस पर खर्च होने वाले 16 करोड़ की तो वह कॉलेनाइज़र तो देने वाला है नहीं लिहाज़ा बिजली विभाग प्रत्येक उपभोक्ता से, नया कनेक्शन देते वक्त, 3 0, 000 रुपये वसूलता है। इस मद में करीब 9 करोड़ तो एकत्र हो चुके हैं, शेष 7 करोड़ भी धीरे-धीरे हो जायेंगे।

इसी तरह की समस्या यहां पानी व सीवर की भी है। पानी के लिये माफ़िया के टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ता है तो सीवर का हाल बेहाल होकर इधर-उधर बह कर बुढिया नाले तक पहुंच जाता है। इस सबके बावजूद सरकार का नगर निगम हाउस टैक्स लेना कभी नहीं भूलता, प्लॉटों के क्रय-विक्रय पर स्टाम्प भी सरकार नहीं छोड़ती। लेकिन इसके बदले नागरिकों को देना कुछ नहीं। उधर कॉलोनाइज़र मेंटेनेंस के नाम पर जो वसूली करता है वह अलग से।

ग्रीनफ़ील्ड की तमाम समस्यायें कोई एक दिन में पैदा नहीं हो गयी हैं। ये 40 बरसों से पैदा होती-होती विभिन्न सरकारों के संरक्षण में फल-फूल कर आज खतरे के स्तर तक पहुंची हैं। सीमा त्रिखा जब वोट मांगने गयी थी और उससे करीब 6 माह पूर्व कृष्णपाल गूजर वोट मांगने गये थे तो ये सब समस्यायें इनको नज़र नहीं आईं थीं? खूब खुल कर जनता ने बताई थी और इन्होंने सत्तारुढ़ होने पर इन्हें हल करने का वायदा भी किया था। लेकिन वायदे तो वायदे ही होते हैं। इन्हें चुनावी ही जुमला भी कहा जाता है।

असल कॉलोनाइज़र बहुत पहले गुजर चुका है

साठ के दशक में लाइसेंस प्राप्त करने वाले असल कॉलोनाइज़र की मृत्यु उपरांत भारत सरकार ने कॉलोनी की देख-रेख एवं संचालन हेतु एक प्राइवेट कंपनी को नियुक्त कर दिया था। यदि यह दायित्व उसी समय हरियाणा सरकार के अर्बन एस्टेट को दे दिया गया होता तो आज ये समस्यायें न हुई होती। विदित है कि रीयल एस्टेट के धंधे में बेतहाशा लूट कमाई होती है। इसीलिये तत्कालीन सरकार ने अपने किसी चहेते को यह जमा-जमाया धंधा सौंप दिया था। इस कंपनी ने, कॉलोनी में बसने वालों के लिये, जो सुविधायें देनी चाहिये थी वे उपलब्ध नहीं करायी।

पिछले कई वर्षों से कॉलोनी वासी कॉलोनी के अधिग्रहण करने के लिये सरकारों पर तरह-तरह से दबाव डालते रहे हैं। लेकिन अपनी मुनाफ़ाखोरी को बनाये रखने के लिये कंपनी ने इसे अधिग्रहीत नहीं होने दिया।

कॉलोनी वासियों की कल्याण समिति के अध्यक्ष बिंदे के पुत्र विवेक ने इस संवाददाता को बताया कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री खट्टर ने उनके लगातार किये जाते अनुरोध को स्वीकार करते हुये कई माह पूर्व इसे अधिग्रहीत करने के आदेश जारी करवा दिये थे। लेकिन नगर निगम व 'हूडा' के स्थानीय अधिकारी उस पत्र को भी दबा कर बैठ गये। अब कुछ अधिग्रहण की कार्यवाही चलने की संभावना है। अधिग्रहण करने से सरकार के कब्जे में करीब 500 करोड़ की वह संपत्ति आ जायेगी जिसे बेचकर कॉलोनी वासियों के तमाम दुखों का निवारण करने के साथ-साथ सरकार को भी मोटा मुनाफ़ा हो पायेगा।